GOVERNMENT BILL

The Post Office Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ashwini Vaishnaw to move a motion for consideration of the Post Office Bill, 2023.

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I move:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to Post Office in India and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय उपसभापति महोदय, 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंड करने के लिए 'पोस्ट ऑफिस बिल, 2023' लाया गया है। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डाक, डाकघर और डाकिया, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन पर देश भर में जन-जन में बहुत बड़ा विश्वास है। एक समय था जब 125 साल पुरानी संस्था के बारे में लग रहा था कि यह irrelevant हो जाएगी, विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था, उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरह से फेज़ आउट करने की नौबत आ गई थी, लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लैक्शन इस नए बिल में है।

माननीय उपसभापति महोदय, पिछले साढ़े नौ वर्षों में डाक, डाकघर और डाकिये को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है। डाकघरों का विस्तार देखें तो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, माननीय उपसभापति महोदय, आपको और सदन को जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 के बीच करीब 5,000 नए डाकघर खोले गए हैं और करीब 5,746 और नए डाकघर खोलने की प्रक्रिया में हैं। 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के ज़रिये कनेक्ट किया गया है। जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ज़न का माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विज़न है, उसी के तहत 434 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में अब तक करीब-करीब सवा करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी हैं। 13,500 डाकघर आधार सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते, जो बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है, उनमें 1 लाख 41 हज़ार करोड़

रुपये अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, हमारी बहनों के साढ़े तीन करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं।

महोदय, आपको एक और बात जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है, जिसके ज़रिये एक रिमोट एरिया से साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकता है। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिससे 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। इसमें ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, कर्णाटक के बेलगाम से एक बहन सृष्टि करंजिनी घर में बने वॉटर कलर अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, श्रीनगर से भाई आदिल अहमद खान गलीचे, रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, असम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं और कोट्टायम, केरल से मैथ्यू जोसेफ नैचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। आज डाकघर के ज़रिये इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, उनका ग्लोबल रिकग्निशन भी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गनाइज़ेशन यूपीयू (UPU) है, उसने अभी रिसेंट्ली स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया है, inclusive growth, inclusive trade के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीयू से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टैक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में एक three-dimensional printed डाकघर बना है। एक नया experiment किया गया, जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून के एवज में जो नया कानून लाया गया है, वह अति सरल भाषा में बना है। यह 17 क्लॉजेज़ का छोटा-सा कानून है और सारा फोकस मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पर और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज़ पर शिफ्ट होने का है।

The question was proposed.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, मैं इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को आमंत्रित करने से पहले एक announcement करना चाहूंगा।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHIRMAN: I have to inform the hon. Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is, on 4th December, 2023, has allotted time for Government Legislative Business as follows:

1. Consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023. — **Six Hours**